भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 541
06 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

नेफेड और एफसीआई के लिए लंबित राशि को जारी करना

541. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान राज्य विपणन निगम लिमिटेड (आरएसएमसीएल) द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों में से मनमानी राशि काट ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास उपरोक्त कटौती के लिए कोई विशेष कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के लिए लंबित राशि को शीघ्रातिशीघ्र जारी करने का निदेश देने का है और यदि हां, तो इसकी समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): जहां तक खाद्यान्न खरीद से संबंधित दावों का संबंध है, राजस्थान एक गैर-विकेन्द्रीकृत खरीद (नॉनडीसीपी) राज्य होने के कारण, अधिकांश खाद्यान्न राज्य सरकार/राज्य सरकार एजेंसियों (एसजीए) द्वारा खरीदा जाता है और खाद्यान्न को केंद्रीय पूल परिचालनों के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सौंप दिया जाता है।

जहां तक राजस्थान राज्य विपणन निगम लिमिटेड (आरएसएमसीएल) का संबंध है, राजस्थान में केन्द्रीय पूल परिचालन के लिए खाद्यान्न की खरीद में ऐसी कोई एजेंसी शामिल नहीं है।

(ग): राजस्थान राज्य सहित राज्यों को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी अनंतिम लागत पत्रक में निर्धारित दर पर प्रस्तुत बिल के आधार पर खाद्यान्नों की खरीद के बदले धनराशि जारी की जाती है। राज्यों को धनराशि जारी करना एक अनवरत और सतत प्रक्रिया है।

*****